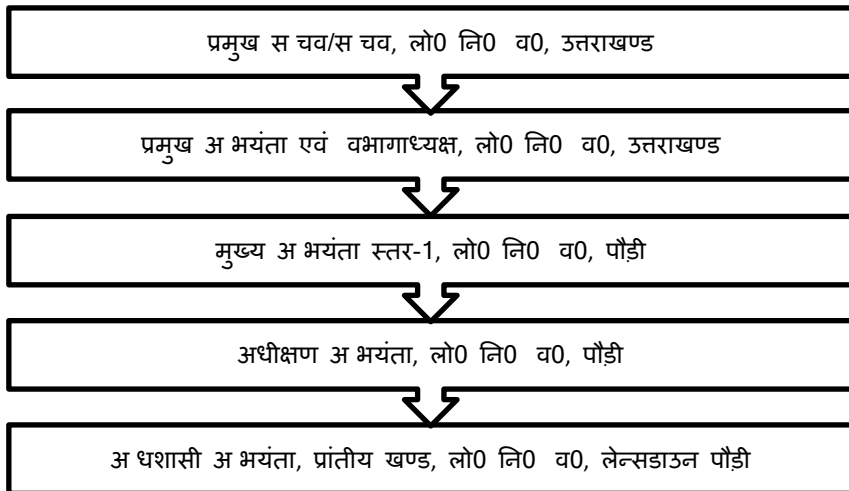


2015-16								
2016-17			587.76	514.36	990.20	990.38		
2017-18 (जनवरी तक)			709.77	651.23	728.84	508.24		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं नाबार्ड के द्वारा क्या जाता है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वधः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधशासी अभ्यंता, प्रांतीय खण्ड, लो० नि० व०, लेन्सडाउन, पौड़ी के माह 08/2016 से 02/2018 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यंता, प्रांतीय खण्ड, लो० नि० व०, लेन्सडाउन, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र लेन्सडाउन (धूमकोट) के अंतर्गत टकोलीखाल-बीरोखाल मोटर मार्ग का निर्माण का वस्तुतः वश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी

एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 09-10-2017 से 12-10-2017 तक का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तक की गई।

5. फार्म 51: माह जनवरी 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-

भाग प्रथम ` 47,224.01

भाग द्वितीय ` 6,66,497.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह फरवरी 2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम ` 81,96,534.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 3,14,13,205.00

(ङ) भण्डार ` 31,02,980.95

भाग दो (ब)

प्रस्तर:1- वतीय नियमों की अवहेलना कर पुनः स्वीकृति लये बिना अधूरे निर्माण कार्य पर व्यय रु. 258.75 लाख

-

-380, Lapse of sanction-The approval

or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded”

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राज्य योजना के अंतर्गत वधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन (धूमकोट) के अंतर्गत टकोलीखाल-बीरोखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1537/III (2)/07-07(प्रा0आ0)/07 दिनांक 13.07.2007 के द्वारा 15.00 कमी हेतु लागत 258.75 लाख की प्राप्ति हुई थी। उक्त कार्य के लंबाई क0मी0 1 से क0मी0 8 तक के भाग की प्रावधक स्वीकृति लागत रु0 258.75 लाख हेतु मुख्य अभ्यंता(गढ़वाल-क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी को दिनांक 15.05.2015 को प्रेषित की गयी। उक्त कार्य की लंबाई क0मी0 1 से क0मी0 8 तक के भाग की प्रावधक स्वीकृति मुख्य अभ्यंता(गढ़वाल-क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्रांक 1160/12(207)याता0-पौड़ी/2015 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा प्रदान की गई। उक्त कार्य के प्रथम चरण को 8 भागों में विभाजित कर पृथक-पृथक अनुबंध गठित किया गया।

कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाउन, पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रश्नगत कार्य की रु0 258.75 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति 15 क0मी0 लंबाई मार्ग हेतु थी परंतु उक्त के सापेक्ष प्रावधक स्वीकृति मात्र 8 क0मी0 हेतु प्रदान करते हुये उक्त धनराश रु0 258.75 लाख की लागत का प्रावधान किया गया। शासन द्वारा 15 क0मी0 लंबाई हेतु स्वीकृत धनराश के सापेक्ष मात्र 8 क0मी0 लंबाई के मोटर मार्ग के निर्माण पर शासन से स्वीकृति लिए बगैर पूर्ण स्वीकृत धनराश खर्च किया गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि शासन की वतीय स्वीकृति प्राप्त होने (07/2007) के 05 वर्ष बाद खंड द्वारा कार्य प्रारम्भ कराया गया (06/2017) जो कि वतीय नियमों का उल्लंघन था क्योंकि वतीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के प्रस्तर 380 में स्पष्ट उल्लेखित हैं कि यदि कार्य स्वीकृति से 5 वर्ष के अंदर प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो पुनः स्वीकृति आपेक्षित है।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त की ओर इंगित करने पर खंडीय आख्या में बतलाया गया कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अलग से कोई स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं है। अधूरे कार्य निष्पादन के संबंध में पूछे जाने पर बतलाया गया कि ग्रामीणों द्वारा कार्य में बाधा, संरेखण विवाद एवं वन भूमि की स्वीकृति न होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने में देरी से दरो में वृद्धि हुई जिस कारण मात्र 8 कमी में ही निर्माण किया गया। लेखापरीक्षा को खंड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पुनः पुनरीक्षित आगणन (15 कमी) तैयार किया जाना चाहिए था एवं शासन की स्वीकृति लेकर कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए था।

अतः अधूरे कार्य निष्पादन, कालातीत स्वीकृति पर कार्य कराने एवं ग्रामीणों को सड़क मार्ग की सुविधा से वंचित रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2. रू0 196862.50 की रॉयल्टी की वसूली न किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 62 दिनांक 18/1/2013 के अनुसार रू0 90.00 प्रति घन मी0 से रॉयल्टी की कटौती किये जाने का प्रावधान था। दिनांक 7 अगस्त 2015 को शासन के पत्रांक संख्या 1207 के अनुसार रू0 90.00 के स्थान पर रू0 200.00 से कटौती किये जाने का आदेश हुआ था। इस आदेशा के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 10/12/2015 को स्थगन आदेशा जारी किया गया था। उस स्थगन आदेशा के सापेक्षा शासन के पत्रांक संख्या 107 दिनांक 22/1/2016 को आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दिनांक 10/12/2015 से रॉयल्टी की कटौती शासन के पत्रांक संख्या 62 दिनांक 18/1/2013 की दरों के अनुसार की जायेगी। तत्पश्चात दिनांक 26/2/2016 को शासन के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 211 में यह आदेशा जारी किया गया कि दिनांक 26/2/2016/ से रू0 194.50 से रॉयल्टी की कटौती की जायेगी। तथा पुनः दिनांक 19 मई 2016 को शासन के पत्रांक संख्या 842 के द्वारा पूर्व में जारी दरों को संशोधित करते हुए रू0 154.00 प्रति घन से कटौती के आदेशा जारी किये गये है। जोकि आतिथि तक प्रचलित है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन की माह 3/2017 में संविदाकारों को भुगतान किये गये व्यय वाउचरों में रॉयल्टी की कटौती रू0 90.00 से ही की गयी है, जबकि कार्य की माप माप पुस्तिका में बढी हुई दरों की अवधि में ली गयी थी। अर्थात जब बढी हुई दरे लागू हो चुकी थी। तो उस तिथि को अवर अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिकाओं में पूर्व दरों से गणना करके देयक बनाकर प्रस्तुत करने का क्या कारण था। यही नही अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा भी उन दरों को ही सत्यापित कर भुगतान संस्तुति एवं भुगतान की कार्यवाही की गयी थी। जबकि प्रत्येक स्तर पर देयक की जाँच उसकी मात्रा एवं दरों से की जाती है। फिर भी ऐसा किया जा रहा जिसके कारण शासन को रॉयल्टी से प्राप्त होने वाली धनराशि रू0 196862.50 से वंचित रहना पडा।

इस सम्बन्ध में विभाग से पूछने पर बताया गया कि तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की जाती हैं, यथाशीघ्र सम्बन्धित वाउचरों में उल्लिखित रॉयल्टी की दरें एवं मात्रा का मिलान कर अवशेष रॉयल्टी की वसूली निर्धारित दरों से कर सम्प्रेक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

विभागीय उत्तर संतोषजनक नही हैं, क्योंकि अधिसूचना संख्या 211 में यह आदेश जारी किया गया कि दिनांक 26/2/2016 से रू0 194.50 से एवं 19.05.2016 से 154.00 की दर से रॉयल्टी की कटौती की जायेगी। अर्थात जब शासन के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तो अवर अभियन्ता द्वारा बिल बनाते समय निर्धारित दरों से कटौती कर संविदाकार को भुगतान क्यों नही किया गया था। यदि विभाग के द्वारा लापरवाही ना की गयी होती तो शासन को हो चुकी राजस्व की क्षति की वसूली पूर्व में ही देयकों से कर ली गयी होती, जिससे शासन को वंचित रहना पडा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3 : 12.50 लाख की एलडी की वसूली न कए जाना।

Clause 4.5 If the whole work upto the forth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

गुमखाल-द्वारिखल-चेलुसेण मोटर मार्ग के पक्कीकरण एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 5862/111(2)/14-25(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा 4 कमी. लम्बाई हेतु 130.63 लाख की प्राप्त हुई। इसकी प्रावधक स्वीकृति अधीक्षण अभयन्ता के पत्रांक 466/935/यातायात-12/2014 दिनांक 25-2-2015 द्वारा दी गई। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 2 अनुबंध (52/EE व 02/एसई-12/15) गठित कए गए। जिस पर अब तक कलु 1.15 करोड़ (अनुबंध संख्या 02/SE में 56.17 लाख + अनुबंध संख्या 52/EE में 58.94 लाख) व्यय कए जा चुके है।

कार्यालय अधशासी अभयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, लेन्सडौन, पौड़ी के अभलेखों की जांच में पाया गया क इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 2 अनुबंध (52/EE व 02/एसई-12/15) गठित कए गए। उक्त अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 08/2015 व 06/2015 थी। आगे लेखापरीक्षा में पाया गया क तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्य अभी तक (जनवरी 2018) अपूर्ण थे व उक्त वलम्ब के लए ठेकेदारों के देयकों से कोई भी कटौती नहीं की गयी थी जो क अनुबंध संख्या 52/EE के लए 625012/ व 2/SE के लए 625262/ बनाता है।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क उक्त कटौती की गयी है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि इकाई द्वारा कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कया व साथ ही ठेकेदारों के देयकों में भी उक्त कटौती का कोई भी उल्लेख नहीं है। अतः 12.50 लाख की एलडी की वसूली न कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: 43,110 का अनियमन भुगतान।

वर्तीय नियमों के अनुसार कोई भी व्यय या भुगतान से पूर्व उसकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

फतेहपुर-डेरियाखाल-लेन्सडौन मोटर मार्ग को पेवर द्वारा पी.सी. से नवीनीकरण की स्वीकृति 229/01 याता (नवीनीकरण)-पौड़ी/2016 दिनांक 29.02.2016 व 1232/01 याता (नवीनीकरण)-पौड़ी/2016 दिनांक 25.05.2016 द्वारा प्राप्त थी। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अनुबंध संख्या 13/SE -13/15 गठित किया गया। अभिलेखों की जांच में पाया कि 43,110 का वचलन की स्वीकृति की स्वीकृति मात्र अधीक्षण अभ्यन्ता स्तर तक की है। जबकि अधीक्षण अभ्यन्ता ने उक्त स्वीकृति मुख्य अभ्यन्ता स्तर पर प्रेषित करने की संस्तुति की थी। उक्त वचलन का भुगतान भी ठेकेदार को किया जा चुका है।

उक्त प्रकरण प्रकाश में लाने पर इकाई ने कोई भी उत्तर लेखापरीक्षा को नहीं दिया।

बिना स्वीकृति के 43,110 के भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 - रु 1.15 करोड़ का अदयोमानक कार्य।

गुमखाल-द्वरिखल-चेलुसेण मोटर मार्ग के पक्कीकरण एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 5862/111(2)/14-25(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा 4 कमी लंबाई हेतु रु 130.63 लाख की प्राप्ति हुई। इसकी प्रावधक स्वीकृति अधीक्षण अभयंता के पत्रांक 466/935/यातायात-12/2014 दिनांक 25-02-2015 द्वारा दी गयी। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 2 अनुबंध (52/EE व 02/SE-12/15) गठित कए गए। जिस पर अब तक कुल रु 1.15 करोड़ (अनुबंध संख्या 02/SE में रु 56.17 + अनुबंध संख्या 52/EE 58.94) व्यय कए जा चुके हैं।

कार्यालय अधशासी अभयंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण वभाग, लेंसडाउन, पौड़ी के अभलेखो की जांच में पाया गया क प्रावधक स्वीकृति के bill of Quantity के item no. 9 (providing and laying seal coat by manual means, sealing coat.....using Type A as per ...) Type A की स्वीकृति की गयी थी जब क दोनों अनुबंध बनाते समय उक्त Type A को बदल कर Type B कर दिया गया व उसके अनुसार ही कार्य कराये गए। उक्त सामग्री के परिवर्तन की स्वीकृति अभी तक (फरवरी 2018) प्राप्त नहीं की गयी थी। इस प्रकार मार्ग पर कराये गए पूर्ण अदयोमानक रहे।

इकाई ने अपने उत्तर में भवष्य में पुनरावृत्त न होने का आश्वाशन दिया है।

अतः 1.15 करोड़ का अधोमानक कार्य का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	46/2002-03	1,2,3,4	-
2.	15/2005-06	1,2	1,2,3,4,5
3.	43/2006-07	1,2	
4.	33/2007-08	1,2,3,4,5	1,2,3
5.	04/2009-10	1,2	
6.	29/2011-12	1	2
7.	02/2013-14	1,2,3	1
8.	68/2015-16	1	1
9.	63/2016-17	1	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			वभाग खण्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रस्तरों के संबंध में बताया गया क उक्त के निस्तारण हेतु दिनांक 22.02.18 को ऑ डट कमेटी मटिंग में म.ले. कार्यालय को अनुपालन आख्या उपलब्ध करा दी गई है अतः प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयंता, प्रांतीय खण्ड, लो० नि० व०, लेन्सडाउन, पौड़ी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) माप पुस्तिका सं. - 305L / 233L / 316L / 328L / 292L / 311L / 304L / 300L / 273L / 313L / 331L / 332L एवं 333(S)

2. सतत् अनिय मतताए:

(i) शून्य

3. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री दिनेश वजल्वाण	अधशासी अभयंता
(ii)	श्री आशुतोष कुमार	अधशासी अभयंता

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता, प्रांतीय खण्ड, लो० नि० व०, लेन्सडाउन, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबन्ध रहे।

(i) सर्व श्री डी एस चौहान, (ii) बलदेव राम, (iii) संदीप सिंह,
(iv) पी एस राणा (v) अंकत गंगवार